



क.रा.बी.नि.
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' State Insurance Corporation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



सत्यमेव जयते

मुख्यालय/Headquarters

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002

Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002

वेबसाइट: www.esic.nic.in / www.esic.in

ईमेल: rajbhasha-hq@esic.nic.in

संख्या : ए-49032/1/2022-रा.भा.

दिनांक : 20-11-2025

सेवा में

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/ क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 25.8.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11034/09/2025- राजभाषा (नीति) का अनुसरण करते हुए महानिदेशक महोदय ने निगम में प्रचलित उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना में निम्नलिखित संशोधन हेतु स्वीकृति प्रदान की है:-

वर्तमान योजना का नाम	संशोधित नाम
सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना	सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना
पात्रता में निम्नलिखित पक्ति को जोड़ा जाता है: 2(2)(ड) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

अतः क.रा.बी.निगम की सभी इकाइयों में भविष्य में उक्त पुरस्कार योजना के संबंध में कार्रवाई/परिपत्र जारी करते समय संशोधित नाम का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही गार्ड फाइल में अनुरक्षित संशोधन पूर्व राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/2013/3/87-रा.भा. (क-2) (सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न) के साथ उक्त संशोधन 2(2)(ड) को अनुलग्न कर सहेज लिया जाए।

इस योजना से संबंधित अन्य नियम व शर्तें तथा प्रोत्साहन राशि पूर्ववत् रहेंगी।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 20-11-2025

18:44:39
(श्याम सुंदर कथूरिया)
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि-

1. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें।
2. गार्ड फाइल

निदेशक (राजभाषा)

11034/09/2025-राजभाषा (नीति)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 25/08.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलतः हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) द्वारा प्रोत्साहन राशि में संशोधन भी किया गया।

2. केंद्र सरकार के कार्यालयों में भौतिक फाइलों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक फाइल प्रणाली अपनाए जाने के कारण फाइलों पर टिप्पण/आलेखन का अधिकांश कार्य डिजिटल हो गया है। अतः योजना के कार्यान्वयन को विस्तार प्रदान करने के लिए विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा. (क-2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

वर्तमान में योजना का नाम	संशोधित नाम
'सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'	'सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना'
पात्रता में निम्नलिखित पंक्ति को जोड़ा जाता है:	
2(2)(ड) इस योजना के तहत कंप्यूटर/ई-ऑफिस में हिंदी में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।	

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


25/08/25
(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त निदेशक (नीति)
दूरभाष: 23438251

सेवा में :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत्त निकायों/उद्घर्मों/अभिकरणों/निगामों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाएं।



1/2

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
8. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।
10. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी ।
13. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव ।
14. अतिरिक्त प्रतियां (20)

724
14.6.88

8
5

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
"पंचतोष" भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली

सं. 49/ 4/1/86-हिन्दी

दिनांक: 6. 6. 88

व ि र ण

पृ. 27
अ. 5

विषय: सरकारी काम-काज में मूल हिन्दी टिप्पण/आशेषन के लिए प्रोत्साहन योजना

उपरोक्त विषय पर इत कार्यालय के ज्ञापन संख्या र. 5011/12-7/84-हिन्दी दिनांक 19.3.85 द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना का अतिक्रमण करते हुए भारत सरकार, उप निदेश, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/12013/3/87-उ.आ. अ. 21 दिनांक 16.2.88 की एक प्रतिलिपि इसके साथ सूचना एवं आवापक चर्चा-बाई के लिए तैयार है जिसमें पूर्व योजना के स्थान पर चर्चा जाने वाली नई प्रोत्साहन योजना को स्प-रेखा दी गई है।

वित्त एवं लेखा प्रभाग ने परामर्श से नई प्रोत्साहन योजना 1.4.1988 से निगम कार्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई योजना के अन्तर्गत पुरस्कार की प्राप्ति तथा मूल्यांकन समिति का गठन पूर्व की भांति ही रहेंगे।

चन्द्रभान शर्मा
हिन्दी अधिकारी

सूचना: यथोपरि

कर्मचारी

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक।
2. निदेशक विधिकार्य, दिल्ली।
3. विधिकार्य अतिरिक्त, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर, नई दिल्ली/झिलमिल, गाहटरा, दिल्ली।
4. निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, पूना।
5. प्रभारसे उप क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गाँवा।
6. प्रभारसे संयुक्त क्षेत्रीय निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर।
7. सभी क्षेत्रीय हिन्दी अधिकारी।
8. सभी क्षेत्रीय लेखा अधिकारी।
9. मुख्यालय के सभी अधिकारी/वाक्ताएं।
10. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां।

452
13/6/88
17/6/88

17/6/88

परिपत्र सं० 21/88

संख्या-II/12013/3/87-रा.भा.क-2

भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
राजभाषा विभाग.

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-3.
दिनांक 16 फरवरी, 1988.

कार्यालय जापन

विषय: सरकारी काम-काज मूल रूप से हिन्दो में करने के लिए प्रोत्साहन योजना ।

इस विभाग के कार्यालय जापन संख्या-I/12013/1/84-रा.भा.क-2 दिनांक 25 मई, 1984 के तहत सरकारी कामकाज में मूल हिन्दो टिप्पणी/आलेखन के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजना जारी की गई थी । इस योजना को और अधिक उदार बनाने के लिए इस विभाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति को 27 मई, 1987 को हुई बैठक में भी हिन्दो में काम करने के लिए प्रोत्साहन योजना में परिवर्तन करने के सुझाव दिये गये थे । इन सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय को सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जो 25 मई, 1984 के कार्यालय जापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहन योजना के स्थान पर चलाई जाएगी । योजना का विवरण इस प्रकार है :-

2. योजना का क्षेत्र

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध और अधोनस्थ कार्यालय अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से इस योजना को लागू कर सकते हैं ।

सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दो में करते हैं ।

17FED1988

2/-

॥ख॥ केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे जो "क" तथा "ख" क्षेत्र ॥ अर्थात् बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ र क्षेत्र तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ॥ में वर्ष में कम से कम 20 हजार शब्द तथा "ग" क्षेत्र ॥ जिसमें "क" व "ख" क्षेत्र के अलावा बाकी सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं ॥ में वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इन्दराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि, भी शामिल किए जाएंगे।

॥ग॥ आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

॥घ॥ हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक हो सामान्य अपना काम हिन्दी में करते हैं; वे इस योजना में भाग लेने के नहीं होंगे।

॥३॥ पुरस्कार-

भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रतिवर्ष उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

॥क॥ केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/सम्बन्धित कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :-

पहला पुरस्कार ॥ 2 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु० 500/-

दूसरा पुरस्कार ॥ 3 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु० 300 /-

तीसरा पुरस्कार ॥ 5 पुरस्कार ॥: प्रत्येक रु० 150 /-

-----3/-

४४४ केन्द्रीय सरकार के विभा विभाग के प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय के लिए स्वतंत्र रूप से :

- पहला पुरस्कार 2 पुरस्कार : प्रत्येक रु 400 /-
दूसरा पुरस्कार 3 पुरस्कार : प्रत्येक रु 200 /-
तृतीय पुरस्कार 5 पुरस्कार : प्रत्येक रु 150 /-
४४५ योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक स्थिति वाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । उदाहरणार्थ अलग क्षेत्र में स्थित आयकर आयुक्त के अधीन सहायक आयकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा रेलवे के मंडल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक आदि का कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र एकक माना जाएगा । रक्षा मंत्रालय या डाकतार विभाग के अधीनस्थ तथा संबन्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी ही स्थिति होगी ।

४५१ पुरस्कार देने के लिए मापदण्ड :

४५१ नूल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक रखे जाएंगे । इनमें से 70 अंक हिन्दी में किए गए काम को मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे ।

४५२ जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारियों को दिए जाने वाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उसके क्रम में ऊपर हैं ।

४५३ प्रतियोगी प्रतिदिन सलग्न प्रपत्र में अपने हिन्दी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेगी । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर अ उच्च अधिकारियों द्वारा स्थापन करने के बाद प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा-जोखा रखता है तो कर्मचारियों को लेखा-जोखा रखना आवश्यक नहीं होगा ।

§ 68 एक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए गए काम का लेखा-जोखा प्रति-हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के माध्यम से मूल्यांकन समिति को प्रस्तुत करेगा यदि प्रति-हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा रखता है तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी और उसे ब्यौरा देना होगा।

§ 68 मूल्यांकन समिति

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, संचालन और पत्रिणी के प्रभारी अवर सचिव और त्रिष्ठ हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। संवद और अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अन्य राजपत्रित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके सदस्य हो सकते हैं। तथापि विभिन्न संबंधित कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार समिति के गठन में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा विवरणों में भी समुचित उल्लेख कर दिया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों का एक सूची कृपया इस विभाग को भी पृष्ठांकित कर दी जाए।
4. इस योजना के चलन पर होने वाले खर्च का वहन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान से लिया जाएगा। विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से पुरस्कार स्विकृत कर सकता है। इस पुरस्कार योजना पर विचार मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपनी सहमति अ.टि.सं. एच-78/ई-111/87, दिनांक 27.1.88 द्वारा दे दी है।
5. यह योजना 1 अप्रैल, 1988 से लागू होगी।
6. तमस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस योजना की

अपने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों में तुरन्त परिचालित करें और अपने मंत्रालय/विभाग में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करें। इसे अपने सभी अंशों और अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस योजना के बारे में तुरन्त अज्ञात करारें और उन्हें भी अपने सभी कार्यालयों में इसे 1 अप्रैल, 1988 से लागू करने के आदेश दें। वे अपने नियंत्रण अधीन उपक्रमों, निगमों आदि को भी इस योजना के बारे में जानकारों दें और उन्हें इस आधार पर अपने कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने के लिए प्रेरित करें।

7. इस संबंध में कोई कार्यवाई की सूचना इस विभाग को कृपया साप्ताहिक शीघ्र ही दी जाए।

प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी: की की समाप्त होने वाले सप्ताह में हिन्दो के मूल काम को साप्ताहिक विवरणों।
विवरणों

क्रम सं०	तिथि	कुल फाइलों, रजिस्टरों आदि की संख्या जिन में हिन्दो में काम किया गया।	हिन्दो में लिखे गए टिप्पण और आलेख के शब्दों की संख्या।	हिन्दो में किए गए और काग सक्षिप्त शब्दों की संख्या।	उच्च अधिकार के हस्ताक्षर सप्ताह में एक बार की संख्या।
1.	2.	3.	4.	5.	6.

गोविन्द दास मोलिया
गोविन्द दास मोलिया
उप सचिव, भारत सरकार



सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. भारत का निर्वाचन आयोग